

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :-श्री हरफूलसिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :-323/2024

जी.सी.एम.एस नंबर :- 2024/323

अपीलाण्ट :-

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

अभिजीतसिंह पुत्र
हिम्मतसिंहजी, कौम
राजपुरोहित निवासी
कुआरडा तहसील आहोर
जिला जालोर (राज.)

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी कुआरडा तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
2. छेलकंबर पुत्री हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित, निवासी कुआरडा तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
3. निर्दोषसिंह पुत्र हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित निवासी कुआरडा तहसील आहोर जिला जालोर (राज.)
4. उषारानी पत्नि हिम्मतसिंहजी, जाति राजपुरोहित, c/o शंकर राजपुरोहित, ई 501. कर्णावटी एपार्टमेंट-2 लांबा नारोल, अहमदाबाद (गुजरात)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आहोर, जिला जालोर



अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट अपील बनाराजगी निर्णय
प्रकरण संख्या 03/2021 दिनांक 19/04/2021 बड़जलास
तहसीलदार आहोर

उपस्थिति :-

1. श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री दौलत मकवाना, श्री मो.शरीफ काजी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांक:- 26.12.2024

1. न्यायालय तहसीलदार, आहोर के प्रकरण संख्या 03/2021 आदेश दिनांक 19.04.2021 बअनवान महेन्द्रसिंह बनाम छेलकंबर वगैरा में पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

26.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

3. बहस वकूलाय सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि -

तहसील आहोर, मौजा कुआरडा में खसरा नंबर 47, 62, 95, 210, 232, 746, 5/825 की खातेदारी श्री हिम्मतसिंह पुत्र चतुर्भुजसिंह राजपुरोहित, निवासी कुआरडा के नाम आयी हुई थी। श्री हिम्मतसिंह का दिनांक 30/03/2020 को स्वर्गवास हो चुका है जिनके अपीलांट व रेस्पोंडेंट नं. 1 लगाय 4 वारिशान हैं।



अपीलांट के द्वारा पटवारी को हिम्मतसिंहाली की मृत्यु को लेकर उनके वारिशानों के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र दिया लेकिन पटवारी के द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू न कर टालमटोली करने लगा तथा पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी ने आपस में मिलावट कर ली तथा ग्राम विकास अधिकारी ने हिम्मतसिंहजी के वारिशान के संबंध में गलत प्रमाण पत्र जारी किया जबकि अपीलांट के द्वारा सरपंच से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसमें अपीलांट व रेस्पोंडेंट नं. 4 को बतौर वारिशान होना प्रमाण पत्र में उल्लेखित है इसके अलावा श्री हिम्मतसिंह ने बैंक के खाते में उषारानी को नोमिनी बनाया गया है जिसका भी दस्तावेज पेश है। इस प्रकार हिम्मतसिंह के कुल पांच वारिश होना स्वीकृत तथ्य है। अपीलांट को रेस्पोंडेंट नं. 3 के द्वारा जोधपुर के न्यायालय में एक दावा लगाने की जानकारी भी अभी हुई है जिसमें हिम्मतसिंह के पांच वारिशान होना उल्लेखित है।

रेस्पोंडेंट नं. 1 लगाय 3 ने हिम्मतसिंह ऊपर वर्णित खसरा नंबर की आराजी को हड़प करने के लिये आपस में मिलावट कर रेस्पोंडेंट नं.1 महेन्द्रसिंह से आवेदन पेश करवाया। ग्राम विकास अधिकारी से वारिशानों का गलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया एवं गांव के मिलने वाले व्यक्ति के झूठे शपथ पत्र पेश करवाये तथा अपीलांट व रेस्पोंडेंट नं. 4 को हिम्मतसिंह के वारिश होना नहीं बताया। जबकि अपीलांट का व रेस्पोंडेंट नं. 4 का क्रमश 1/5, 1/5 खातेदारी हक बनता है। रेस्पोंडेंट नं. 5 तहसीलदार ने आपत्ति इशतिहार जारी करना पत्रावली में बताया है लेकिन आपत्ति इशतिहार भी जारी होना नहीं पाया जा रहा है। महेन्द्रसिंह रेस्पोंडेंट नं. 1 ने अपना झूठा शपथ पत्र पेश किया। और झूठे शपथ पत्र में हिम्मतसिंह के केवल तीन वारिशान होना बताया जो प्रथमदृष्टया ही गलत है। यहां यह लिखना उचित है कि श्री हिम्मतसिंह का स्वर्गवास अहमदाबाद में हुआ था जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया तथा वास्तविक वारिशानों के संबंध में जांच तक नहीं की जो प्रावधानों के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र महेन्द्रसिंह, शैलेन्द्रसिंह, जालमसिंह, नैनसिंह व डूंगरसिंह वगैराह के शपथ पत्र झूठे हैं और उक्त शपथ पत्र पेशकर्ता रेस्पोंडेंट नं. 1 में रूचि रखने वाले व्यक्ति हैं जबकि पटवारी हल्का कुआरडा को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि श्री हिम्मतसिंह के पांच वारिशान है तथा अपीलांट के द्वारा म्यूटेशन

26/12/2024
अतिरिक्त सभागीय अधिवक्ता
पाली (राज.)



भरने के संबंध में आवेदन भी कर रखा है लेकिन पटवारी ने मिलावट कर तहसीलदार के समक्ष सही तथ्य उजागर नहीं किया तथा तहसीलदार ने भी पटवारी से रिपोर्ट नहीं मंगवाई हैं जो कानून का उल्लंघन हैं। उपरोक्त आधारों पर रेस्पोंडेंट नं. 5 के द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 19/04/2021 निरस्त करने योग्य हैं तथा उसके आदेश की पालना में यदि म्यूटेशन कर दिया है तो उसे निरस्त करना न्यायसंगत हैं।

दिनांक 20/04/2021 से राज्य सरकार के आदेश से कोविड-19 को लेकर लॉक डाउन प्रभावी हो गया था जो लॉक डाउन दिनांक 28/06/2021 तक प्रभावी हैं। अपीलांत को दिनांक 06/06/2021 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तब अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 07/06/2021 को नकल का आवेदन किया जो नकल दिनांक 10/06/2021 को प्राप्त हुई तथा जानकारी से एक माह के भीतर अपीलांत के अपील पेश करने की म्याद हैं तथा माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने भी लॉक डाउन अवधि को बढ़ाया है जिससे अपील अन्दर म्याद हैं। लॉक डाउन अवधि में अधिवक्ता एवं पक्षकारों की उपस्थिति नहीं होने का भी माननीय राजस्व मंडल अजमेर का परिपत्र हैं।

अपीलांत के विद्वान वकील द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्न विधिक दृष्टांत पेश किये-

1. 2000SAR(civil)778 Para 15 & 18 admission – forming basis of judgement
2. 77SC 1724 admission Burden shift on person who made admission that admission is wrong.
3. 1997 RRD 177

अतः अपील अपीलांत पेश कर निवेदन हैं कि अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19/04/2021 को निरस्त करावे एवं अधिनस्थ न्यायालय को सही जांचकर अपीलांत व रेस्पोंडेंट नं. 4 के नाम म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि -

मौजा कुआरडा तहसील आहोर जिला जालोर में वर्तमान खसरा नम्बर 47, 62, 91, 210, 232 746, 5/825 की कृषि भूमि प्रार्थी के पिता हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह राजपुरोहित निवासी कुआरडा के नाम दर्ज है। अप्रार्थी के पिता हिम्मतसिंह पुत्र का देहान्त दिनांक 30.03.2020 को हो चुका है। हिम्मतसिंह के वारीसान प्रार्थी व अप्रार्थीगण है। इनके अलावा कोई वारीस नहीं है। केवल मृत्यु अहमदाबाद होने के कारण हल्का पटवारी फौतेदगी म्यूटेशन नहीं भर रहे है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर ने नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 के पिताजी हिम्मतसिंह के स्थान पर उनके वारीसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश फरमावे। मृतक हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह के नाम मौजा कुआरडा में दर्ज खसरा नम्बर 47, 62, 91, 210, 232, 746 5/825 में नामान्तरकरण दर्ज करने बाबत राष्ट्रीय अखबार दैनिक नव ज्योति के संस्करण में छाया करवाकर आपत्ति चाही गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा काफी लम्बे समय तक जवाब आदि पेश नहीं किये। महेन्द्रसिंह पुत्र हिम्मतसिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार हिम्मतसिंह पुत्र चर्तुभुजसिंह की

26/12/2024
अभिजितसिंह संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अपीलांट अभिजीतसिंह के विरासत कथन बाबत् तहसीलदार द्वारा समुचित जांच नहीं की गई।

- II. प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा एक सिविल वाद जो जिला एवं सेशन न्यायालय महानगर जोधपुर में निर्दोषसिंह (रेस्पो.3) द्वारा प्रस्तुत किया गया है की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत हुई है जिसके अनुसार रेस्पोडेण्ट निर्दोषसिंह ने अपीलाण्ट अभिजित सिंह एवं उसकी माता रेसपो. स. 4 उषा रानी को मृतक हिम्मतसिंह का वारिस माना है। साथ ही मृतक हिम्मतसिंह की राजकीय सेवानिवृत्ति पर पेशान भी रेस्पो. स. 4 उषारानी को मंजूर होने का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह समस्त तथ्य मृतक हिम्मतसिंह के जायज वारिसान की जांच के समय ध्यान में रखने जाने योग्य है। अतः विधिक वारिसानो की पुनः जांच करवाई जाना आवश्यक है।
- III. विधि का यह सिद्धांत भी सुस्थापित हो चुका है कि संतान के जायज अथवा नाजायज होने से वारिसान के हको पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है, बशर्ते कि पक्षकार के मृतक पिता /माता की संतान होना प्रमाणित हो। इस प्रकरण में भी रेस्पोडेण्ट निर्दोष सिंह द्वारा उक्त वर्णित सिविल वाद में अपीलांट अभिजित सिंह का मृतक हिम्मत सिंह का वारिस होने का स्वीकारोक्ति ADMISSION है। इस संदर्भ में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है।
- इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधिन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधि के प्रावधानो के अनुसार सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।
- IV. उक्त प्रकरण के आलोक में राजस्व प्रशासन के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा विधिक प्रकरणों में प्रकरणों के निस्तारण में की जाने वाली लापरवाही बाबत् प्रशासनिक समीक्षा भी की जानी आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर द्वारा पत्रावली दर्ज करने से लेकर त्रुटिपूर्ण निस्तारण को प्रशासनिक दृष्टि से देखे जाने की आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय में कही भी अंकित नहीं किया गया है कि नामान्तरकरण सुनवाई प्रकरण किस नियम या अधिनियम के तहत सुना जा रहा है। हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में पटवारी हलका को दिनांक 07.12.2020 को प्रार्थना पत्र का क्या निस्तारण किया गया ? एवं प्रकरण में यदि पटवारी हलका से रिपोर्ट ली जाती हैं तो दिनांक 07.12.2020 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नजरअदाज नहीं किया जा सकता था। पत्रावली में न ही प्रार्थी, अप्रार्थी एवं हल्का पटवारी के नाम के नोटिस पर तामील/अदम तामिल की कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। तहसीलदार आहोर द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। पटवारी को नोटिस के द्वारा सुचित (तामील) ही नहीं हुआ है कि प्रकरण में क्या सूचना देनी है। जबकि तहसीलदार, आहोर ने अपने निर्णय



अभिजितसिंह
12.12.2024
अधीनस्थ न्यायालय
जयपुर (राज.)

में लिखा है कि पटवारी हल्का निम्बला से हिम्मतसिंह वल्द चर्तुभुजसिंह के वारीसानो की सूची मंगवाई गई तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपिया मंगवाई गई। तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हल्का पटवारी निम्बला द्वारा प्रस्तुत रेकर्ड पत्रावली में शामिल होना चाहिए था परन्तु उक्त रेकर्ड नहीं है। अखबार में प्रकाशन की स्थिति तब पैदा होती है जब बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी, निम्बला एवं सरपंच, ग्राम पंचायत निम्बला के उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र में भी भिन्नता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार आहोर द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर पत्रावली का निस्तारण करके प्रार्थी रिसपोडेंट महेन्द्र सिंह को अनुचित फायदा पहुंचाते हुए पक्षकारों के मध्य अकारण ही लिटिगेशन को बढ़ावा दिया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानों के अनुसार नहीं सुना गया। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया न्यायिक प्रक्रिया एवं लिटिगेशन को बढ़ाने की होती है। इस प्रकरण में जिला कलक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है प्रशासनिक स्तर पर भी प्रकरण के पत्रावली एवं उससे जुड़े हुए तथ्यों के आलोक में तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय की विस्तृत जांच उपखण्ड अधिकारी के स्तर जांच करवाई जावे। एवं दोषी पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। तकि भविष्य में इस प्रकार से फाल्स लिटिगेशन नहीं बढे।



अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आहोर के प्रकरण सं. 03/2021 निर्णय दिनांक दिनांक 19.04.2021 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, आहोर को प्रकरण इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपीलान्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करे एवं जिला कलक्टर जालोर प्रकरण मे दोषी अधिकारी/कामिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चत करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

28.12.2024
अभिजितसिंह संघर्षीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-इजलास सुनाया गया।

28.12.2024
अभिजितसिंह संघर्षीय आयुक्त
पाली (राज.)